(छ) जी, नहीं ।

(ज) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

2252 थो विठंठलभाई मोती राम पटेल : क्या जल मूतल परिवहन मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में वर्ष 1991–92 और 1992–93 के दौरान गुजरात से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है और ये प्रस्ताव किस क्षेत्र भौर किस सडक से संबंधित हैं ;

(ख) संस्वीकृत प्रस्तावों का ैब्यौरा क्या है और उनके लिए कितने धन का प्रावंटल किया गया है ;

(ग) राज्यों के उन राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिनका विकास किया जाएगा / जिनकी सरम्मत की जाएगी ब्रौर ब्राठवीं पंचवर्षीय योजना ब्रवधि में जिन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) राज्य सरकार को संशोधन के लिए वापस किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने प्रस्ताव वापस मिल चुके हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ड.) शेष प्रस्तावों के संबंध में स्थिति क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय राज्य मंत्रो (धो जगदीश टाइटलर): (क) से (ड.) 1991-92 और 1992-93 के दौरान (30-6-92) तक राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए गुजरात राज्य सरकार से कुल 72 ग्रनुमान प्राप्त हुए ये। क्षेत्रवार ब्यौरें विवरण में दिए गय है। (नीचें देखिए) इनमें से 40 ग्रनुमानों को स्वीक्वति दी जा चुकी है जिनके ब्यौरे तथा उनके लिए किए गये प्रावंटनों का ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है (नीचें देखिए) शेष ग्रनमानों में से 19 भ्रनुमानों को स्पष्टीकरण हेतु राज्य सरकार को लौंटा दिया गया था श्रौर 13 अनुमानों पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) संवैधानिक दृष्टि से केंद्र सरकार मुलतः केंवल राष्ट्रीय राजमागौं के रूप में घोषित सडको के लिए ही जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों सहित ग्रन्य सभी सडकों के विकास और रख-रखाव के लिए श्रनि-वार्यतः संबंधित राज्य सरकारें ही जिम्मे-दार हैं। ग्राठवीं योजन्ग के दौरान नए राष्ट्रीय राजमागों को घोषणा के संबध में विभिन्न राज्य सरकारों ने लगभग 37,566 कि॰ मी॰ के कूल 135 प्रस्ताब भेजे हैं। इनमें गजरात सरकार द्वारा भेजे गए 2271 कि॰ मी॰ लंबाई के 9 प्रस्ताव भी शामिल हैं। निर्धारित मानदंड के ग्रनसार इन् प्रस्तावों की विस्तुत जांच करने के प्रयोजन से राज्य सरकार से धनरोध किया गया था कि व निर्धारित प्रांत में प्रत्येक प्रस्ताब के बारे में पूरे व्यौरे ग्रौंचित्य इत्यादि संबंधी सूचना भेंजे । उनके राज्यों में यह सूचना ग्रभी नहीं भंजी है। संसाधनों का भी ग्रभाव है। इस लिए ग्राठवीं योजना में नए राष्ट्रीय राज-मार्गों के बारे में ग्रभी से निर्णय लेना संभव नहीं है ।

विवरण-]

वर्ष 1991–92 या 1992–93 के दौरान गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की क्षेत्रवार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-वार स्थिति ।

क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	प्रस्तावों संख्या	
उत्तरी गुजरात	8, 8सी, 14,15	19	
दक्षिणी गुजरात	8, 8ए	36	
सौराष्ट्र	8ए, 8बी	15	
নন্দ্ত	8 ए, 15	2	
	योग :	 72	

विवरण-∏

वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों मैं से म्रस्वीक्रुत प्राक्कलनों की स्थिति

कार्यका नाम	प्राक्कूलनों की। संख्या	(रुपए करोड़ में) ,		
		संस्वी कृ ति	आवटन 1991-92	ग्रावंटन 1992-93
4 लेनों का बनाना	1	3.44)		
गैंदल पथ को सुदढ़ करना ं	10	17.10	1.67	**
पुल तथा पहुंच मार्ग	1	2.45		· · · · ·
বিবিধ	28	4. 81		
ະ	40	27.89		

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न विकास कार्यों तथा पिछले वर्षों से चल र हे कार्यों एवं चालू वर्ष के दौरान स्वीक्वत किए जाने वाले नए कार्यों के लिए 1992-93 के दौरान 42.00 करोड रु० का अनस्तिम तौर पर आवटन किया गया है। वर्ष के दौरान काय-वार आवटन, कार्यों की प्रगति, निधियों की उपलब्धता तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गए व्यौरों के आधार पर किया जाता है।

Loss due to Transporters Strike

2253. SHRI CHIMANBHAI MEHTA :

SHRI SOM PAL : SHRI SARADA MOHANTY : SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN : DR. SANJAYA SINH :

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry has consulted Attorney-General on the feasibility of suing States and Union Territories that persist in levying octoroi and toll tax, if so, the outcome thereof ;

(b) whether it is a fact that over Rs. 1000 crores is being wasted annually at the check-posts by way of loss of diesel, apart from huge administrative expenditure ;

(c) whether the All-India Motor Transport Congress had gone on strike from the 1st July, 1992; if so, what were its effects on the economy of the country, particularly losses suffered by industries labour and exporters as a result thereof;

(d) what action Government have taken to compensate the above losses; and

(c) whether any steps are being taken to re solve the issue ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SUR-FACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) Yes, Sir.